बताया
नैनीताल में उत्तराखंड का उच्च न्यायालय
2022 का सिविल पुनरीक्षण संख्या 52
अरुण विजय सती... प्रतिवादी/पुनरीक्षणकर्ता
बनाम
दिनेश चंद्र थपलियाल और अन्य... वादी/जवाबकर्ता

अधिवक्ता: श्री अरविंद वशिष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता, संशोधनवादी के लिए श्री इमरान अली, अधिवक्ता द्वारा सहायता प्राप्त।

माननीय शरद कुमार शर्मा, जे.
दलीलों का जवाब देने से पहले, जैसा कि पुनरीक्षणकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा बताया गया है, यह न्यायालय उन परिस्थितियों से निपटने के लिए उपयुक्त महसूस करता है, जिसके तहत दिनांक 5 जून 2022 का विवादित आदेश, जैसा कि सिविल सूट संख्या 2022 में दिया गया है। 2017 का 1, दिनेश चंद्र थपलियाल और अन्य बनाम। रमेश चंद्र थपलियाल और अन्य, नीचे के न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसमें दो मुद्दे सीपीसी की धारा 11 के निहितार्थ के संबंध में अंक संख्या 8 और संस्था के बार को आकर्षित करने के संबंध में मुद्दा संख्या 9 थे। सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत मुकदमे की कार्यवाही में प्रतिवादी/पुनरीक्षणवादी के खिलाफ विवादित आदेश द्वारा जवाब दिया गया है, जो चुनौती के अधीन है।

2. वर्तमान मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि पहले एक सिविल सूट, 1992 के सिविल सूट संख्या 41, रमेश चंद्र थपलियाल बनाम। श्रीमती देवेश्वरी देवी और अन्य, प्रावधानों को लागू करके सिविल जज, पौड़ी गढ़वाल के न्यायालय के समक्ष स्थापित किया गया था

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 और 38 के तहत निहित, जिसमें "विषय वस्तु", जिसे पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा तर्क दिया गया है, जैसे कि विषय वस्तु "संपत्ति शामिल" होगी, अर्थात गाँव में पड़ी जमीन श्रीकोट, गंगानाली, पट्टी कतुलस्युं खतौनी खाता संख्या 27, ग्राम कोटेश्वर की 6 नाली 9 मुट्ठी, खाता संख्या 8 में पड़ी भूमि जिसमें से 15 नाली ग्राम कोठड़, कटुलस्युं खसरा संख्या 7/8, 4 नाली में स्थित है 5 मुट्ठी और 14 नाली 3 मुट्ठी के क्षेत्र के खाता संख्या 45 में पड़ी भूमि की भी, उपरोक्त 5 खाता संख्या में से; 8 जून 1992 को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के न्यायालय के समक्ष स्थापित शेयरों के विभाजन के डिक्री के अनुदान के लिए एक सूट में कुल 44 नाली 2 मुट्ठी भूमि विवाद का विषय थी। मुख्य अनुतोष निम्नानुसार है: -

"अनुतोष

(अ) प्रतिवादी सं0 1 के नाम नगरपालिका श्रीनगर के अभिलेखों में अंकित व नन्दा देवी मोहल्ला, गुरूद्वारा रोड़ श्रीनगर मे स्थित दादरसी भवन का बंटवारा कर वादी का उसमें 1/5 दादरसी मालिकाना हक हिस्सा घोषित कर अलग किया जाए।

(ब) यह कि, वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरूद्ध ग्राम कोठड़ के खाता सं. 44 में प्रतिवादल सं0 1 के नाम शेष दादरसी 3 नाली 10 मुठ्ठी व ग्राम श्रीकोट, गंगानाली, पट्टी–कटूलस्यूं के खाता सं0 27 में शेष दादरसी 2 नाली 8 मुठ्ठी कुल 6 नाली 2 मुठ्ठी भूमि पर वादी का दादरसी मालिकाना 1/5 हक घोषित किया जाए।"

3.वास्तव में अनुतोष की प्रकृति, जिसे 1992 के उक्त वाद में संशोधित किया गया था, अधिकार के संबंध में एक घोषणा थी, जिसके बारे में कहा गया था कि इसे हस्तांतरित करने का दावा किया गया था विवादित संपत्ति के 1/5 वें हिस्से की सीमा,और उक्त मुकदमे में प्रतिवादियों के खिलाफ घोषणा की डिक्री भी मांगी गई थी। इसके अलावा, इस आशय की एक घोषणा भी मांगी गई थी कि उन्हें विवादित संपत्ति का मालिक घोषित किया जा सकता है, जो मुकदमे में विवादित थी।

4. 1992 का मुकदमा संख्या 41, संपत्ति के संबंध में घोषणा की डिक्री की मांग करते हुए, जिसे ऊपर निपटाया गया है, उसमें वादी यानी श्री रमेश चंद्र थपलियाल के पक्ष में फैसला किया गया था, और यह तर्क दिया गया है कि शीर्षक की घोषणा के उक्त निर्णय ने अपनी अंतिमता प्राप्त कर ली है। बाद में, यह तर्क दिया गया, कि उसी विवादित संपत्ति के संबंध में कार्यवाही का एक और सेट था यानी 2009 के सूट नंबर 16 के माध्यम से, जिसके तहत 3 जुलाई 2009 को बिक्री विलेख को चुनौती दी गई थी। उक्त बिक्री विलेख संपत्ति के उसी सेट के संबंध में कहा गया था, जो पहले के वाद संख्या की विषय वस्तु थी। 1992 का 41, और परिणामस्वरूप, यह 2017 के वाद संख्या 1 होने के कारण वर्तमान मुकदमे का विषय भी था।

5. वादी 2017 के सूट नंबर 1 दिनेश चंद्र थपलियाल और अन्य बनाम रमेश चंद्र थपलियाल और एक अन्य ने 1963 के विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 38 के साथ पढ़ने के लिए धारा 31 के प्रावधानों को लागू करके, बिक्री विलेख को रद्द करने के डिक्री के अनुदान के लिए मुकदमा दायर किया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि 22 सितंबर 2016 को निष्पादित उसमें प्रतिवादी 22.09.2016 के बिक्री विलेख को कानून की दृष्टि से शून्य और अवैध घोषित करने के लिए उक्त मुकदमे की स्थापना पर प्रतिवादी कौन थे, उन्होंने 7 दिसंबर 2019 को दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के तहत एक आवेदन दायर किया था,यह तर्क देते हुए कि 2017 का वर्तमान सिविल सूट नंबर 1, जहां चुनौती 2016 के बिक्री विलेख तक ही सीमित थी, को न्याय-निर्णय के सिद्धांत द्वारा वर्जित किया जाएगा, क्योंकि विषय वस्तु, यानी विक्रय–विलेख, जो पुनरीक्षणवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील की धारणा के अनुसार, संपत्ति होगी, जो कि पहले के मुकदमे में घोषणा की विषय वस्तु थी, जो कि 1992 का मुकदमा संख्या 41 था, जो एक विषय वस्तु के रूप में भी रहा जब 2009 के सूट 16 में बिक्री विलेख दिनांक 3 जुलाई 2009 को चुनौती दी गई थी, जैसा कि पैरा 8 में उनके आवेदन में संदर्भित है, जो कि प्रतिवादी/पुनरीक्षणवादी द्वारा नीचे के न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था, और उसके बाद, यह तर्क दिया गया था कि विवादित संपत्ति पर अधिकार की घोषणा के पहले के फैसले के साथ-साथ बिक्री विलेख के कारण, जिसे 2009 के सूट संख्या 16, 2017 के तत्काल सूट संख्या 01 में माना गया था, जहां चुनौती दी गई थी बाद की बिक्री विलेख, जिसे 22.09.2016 को निष्पादित किया गया था, न्याय निर्णय के सिद्धांतों द्वारा वर्जित होगा, और इसलिए सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 लागू होंगे।

6. प्रतिवादी/पुनरीक्षणवादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यदि धारा 11 की भाषा को ध्यान में रखा जाता है, तो धारा 11 के तहत जो शक्ति सृजित की जाती है, वह यह होगी कि "किसी भी मुकदमे या किसी मुद्दे का प्रयास करना", जिसमें मामला सीधे या पर्याप्त रूप से, मुद्दा का विषय रहा हो पूर्व सूट में। प्रतिवादी/पुनरीक्षणवादी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा विस्तारित धारा 11 की यह व्याख्या, उनके अधिकारों के निर्धारण के अनुरूप होगी, जो घोषणा के लिए पहले के मुकदमे में तय किया गया था, जिसका दावा है कि यह एक विरोध के रूप में काम करेगा क्योंकि यह एक ऐसा मुद्दा था, जिसे पहले 1992 के मुकदमे संख्या 41 में तय किया गया था।

7. इस न्यायालय का विचार है, कि धारा 11 के तहत इस्तेमाल की जाने वाली भाषा जहां "किसी भी मुकदमे या मुद्दे का प्रयास करेगी" का अर्थ हमेशा विषय वस्तु यानी संपत्ति नहीं होगा, बल्कि कार्रवाई का कारण होगा, जो वादी को प्राप्त हुआ है, बाद के मुकदमे को स्थापित करने के लिए। यहां, वर्तमान मामले में बाद का मुकदमा, कार्रवाई का कारण या मुद्दा, जो अर्जित किया गया है, बिक्री विलेख दिनांक 22.09.2016 के निष्पादन के परिणामस्वरूप है, जो पुनरीक्षणवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है, कि यदि वह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, तो 22.09.2016 के विक्रय विलेख को चुनौती देने के लिए, 2017 के सूट संख्या 01 में, यह पहले के डिक्री के प्रभाव को समाप्त कर देगा, जो 1992 के सूट संख्या 41 में दिया गया था , संपत्ति के 1/5 वें हिस्से की सीमा तक अधिकार की घोषणा के लिए।

8. सीपीसी की धारा 11 के तहत निहित प्रावधान की शब्दावली, जहां विधायिका ने मामले में 'किसी भी मुकदमे या मुद्दे का प्रयास' किया है। इसमें प्रयुक्त शब्द "मुद्दे" के अर्थ का व्यापक प्रभाव होगा, और विशेष रूप से, यदि इसे निर्णय के संदर्भ में पढ़ा जाए, जैसा कि 2005 (1) एससीसी 787, भानु कुमार जैन बनाम अर्चना कुमार व अन्य में रिपोर्ट किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय ने एस्टोपेल और रेस-जुडिकाटा के मुद्दे के बीच अंतर किया है। Res-judicata थैलेसिक का निर्धारण करने के लिए न्यायालयों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से रोकता है, अगर इसने पार्टियों के बीच अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है। जबकि, एस्टॉपेल जारी करने के सिद्धांत को पार्टी के खिलाफ तभी लागू किया जाता है जब ऐसा कोई मुद्दा उसके खिलाफ हो या पहले ही तय हो चुका हो, उसे बाद की कार्यवाही में इसे उठाने से रोक दिया जाएगा। Res-judicata का सिद्धांत एक अलग तरह का विबंधन बनाता है, न कि किसी न्यायालय द्वारा विबंधन जब यह कार्रवाई के कारण से संबंधित होता है।

9. वास्तव में, यदि चुनौती के तहत आक्षेपित आदेश को ध्यान में रखा जाता है और विशेष रूप से, टिप्पणियों के संदर्भ में, जो कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पैरा 11 और विशेष रूप से निर्णय के पैरा 13 में अपने निष्कर्ष दर्ज करते समय किया गया है, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने सही निष्कर्ष निकाला है, कि पहले के दो वादों में, "कार्रवाई का कारण" पूरी तरह से अलग था, क्योंकि 1992 के वाद संख्या 41 में, यह 1/5 से अधिक शीर्षक की घोषणा का अधिकार था।

उक्त मुकदमे की कार्यवाही के लिए पक्षों के बीच अंतर्विरोध, और 2009 के मुकदमे संख्या 16 में, यह एक विषय वस्तु थी, जो 3 जुलाई को बिक्री विलेख के निष्पादन के कारण पूरी तरह से अलग कार्रवाई का कारण उत्पन्न करती है।

10. उस सूरत में, इस न्यायालय का विचार है, कि धारा 11 को आकर्षित करने के प्रयोजनों के लिए, "मुद्दे" को "कार्रवाई के कारण" के रूप में निरूपित किया जाएगा, जो बाद के संस्थान के मुकदमे में वादी को प्राप्त होता है। वर्तमान मामले में, कार्रवाई का कारण, बाद के बिक्री विलेख के परिणामस्वरूप है, जिसे 22 सितंबर 2016 को निष्पादित किया गया था, जो कि इस न्यायालय की राय के अनुसार पूरी तरह से अलग मुद्दा होगा, और बाद की कार्रवाई का कारण, जैसा कि यह संबंधित है बाद के क्रेता के अधिकार के निर्धारण के लिए।

11. वास्तव में, पुनरीक्षणवादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आक्षेपित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में दी गई व्याख्या, कि वास्तव में जब अधिकार एवं शीर्षक की दृष्टि से 1/5 हिस्सा 1992 के मुकदमे में पहले ही निर्धारित किया जा चुका है तो वह वर्तमान मुकदमे की संस्था को प्रतिबंधित कर देगा।

12. इस न्यायालय का विचार है, कि "मुद्दे" शब्द, जिसे सीपीसी की धारा 11 के तहत संदर्भित किया गया है, को तर्कसंगत रूप से व्याख्या करना होगा, "मुद्दा" हमेशा निरूपित करेगा न कि विषय वस्तु का, सूट यानी विवाद में संपत्ति या पहले के मुकदमे में अधिकार के निर्धारण का विषय, घोषणा के लिए मुकदमे के माध्यम से भी, इस न्यायालय की राय है कि यहां मुद्दा "कार्रवाई का कारण" होगा। यह पूरी तरह से कार्रवाई का एक नया कारण जो वादी / प्रतिवादी के लिए मुकदमा शुरू करने का कारण निर्धारित करेगा, जैसा कि विक्रय विलेख, जिसमें, प्रतिवादी/आवेदक के लिए धारा 11 के तहत आवेदन करने के लिए हमेशा खुला रहेगा।

13. कानूनी बोलचाल में, विषय वस्तु हो सकती है, कि यह वही संपत्ति योग्यता है, जिसके अधिकारों को प्रतिवादी/पुनरीक्षणवादी के पक्ष में पहले की कार्यवाही में घोषित किया गया है, लेकिन वह घोषणा स्वयं इस मुद्दे को कम नहीं करेगी, यदि 22 सितंबर 2016 के बाद के बिक्री विलेख के निष्पादन के कारण बाद का कारण बनता है, क्योंकि 1992 के सूट संख्या 41 में दी गई डिक्री का क्या असर हो सकता है, यह हमेशा तय की जाने वाली विषय वस्तु होगी 22 सितंबर 2016 को बिक्री विलेख के औचित्य की जांच करते हुए, और डिक्री के प्रभाव को जारी करते हुए, ट्रायल कोर्ट द्वारा तथ्यों की सराहना के आधार पर एक मुद्दे के रूप में, केवल एक विषय वस्तु होगी जिसका निर्णय किया जाना है न्यायालय, 1992 के वाद संख्या 41 में घोषणा के वाद में प्रदान की गई डिक्री के प्रभाव के बारे में एक उपयुक्त मुद्दे को विरचित करते हुए।

14. पुनरीक्षणवादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय का उल्लेख किया है, जैसा कि 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 888, आर.एम. सुंदरम उर्फ मीनाक्षीसुंदरम बनाम श्री कयारोहणसामी और नीलायाधाक्षी अम्मन मंदिर, और विशेष रूप से पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने उक्त निर्णय के पैरा 36 की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है, जिसे यहां उद्धृत किया गया है:-

"36 संहिता की धारा 11 के तहत रेस जुडिकाटा के सामान्य सिद्धांत में फैसले की निर्णायकता के नियम शामिल हैं, लेकिन रेस जुडिकेटा को लागू करने के लिए, बाद के मुकदमे में सीधे और पर्याप्त रूप से विवाद का मामला वही होना चाहिए जो सीधे और काफी हद तक विवाद में था। इसके अलावा, वाद को योग्यता के आधार पर तय किया जाना चाहिए था और निर्णय को अंतिम रूप प्राप्त करना चाहिए था। जहां पूर्व मुकदमे को क्षेत्राधिकार की कमी के लिए, या वादी की उपस्थिति में चूक के लिए, या पार्टियों के गैर-संयोजन या गलत-संयोजन या बहुपक्षीयता के आधार पर, या इस आधार पर कि सूट को बुरी तरह से फंसाया गया था, के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है, या एक तकनीकी गलती के आधार पर, या वादी की ओर से प्रोबेट या प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफलता के लिए जब वादी को डिक्री का हकदार बनाने के लिए कानून द्वारा आवश्यक हो, या सुरक्षा प्रदान करने में विफलता के लिए लागतों के लिए, या अनुचित मूल्यांकन के आधार पर, या एक वादपत्र पर अतिरिक्त न्यायालय शुल्क का भुगतान करने में विफलता के लिए, जो कम मूल्यांकन किया गया था, या कार्रवाई के कारण के अभाव में, या इस आधार पर कि यह समय से पहले है और बर्खास्तगी की अपील में पुष्टि की गई है (यदि कोई हो), निर्णय गुण-दोष पर नहीं होने के कारण, बाद के मुकदमे में न्यायिक नहीं होगा। इसका कारण यह है कि पहले मुकदमे का फैसला गुण-दोष के आधार पर नहीं किया गया है।

15. विशेष रूप से उक्त का सन्दर्भ संहिता की धारा 11 के प्रभाव के संबंध में किया गया है, जिसे उक्त निर्णय द्वारा ऊपर निपटाया गया है, यह उन टिप्पणियों के कारण था जो न्यायिकता के सामान्य सिद्धांतों के माध्यम से की गई थीं । इसमें निर्णय के निष्कर्ष के नियम शामिल हैं और संबंधित हैं। यहां, निर्णायकता "कार्रवाई के कारण" के पहलू के रूप में होगी, न कि "संपत्ति की विषय वस्तु" के रूप में, जो कि घोषणा में पहले के वाद में प्रतिवादी/पुनरीक्षणवादी के पक्ष में किए जाने का आरोप लगाया गया है।

16. मामले का प्रत्यक्ष या पर्याप्त रूप से संदर्भ, एक मुद्दा, कार्रवाई के कारण के लिए एक बाधा नहीं होगी , बल्कि पहले की गई घोषणा होगी। चूंकि मौजूदा मुकदमे में प्रतिवादी/पुनरीक्षणवादी के अधिकार की घोषणा का कोई तत्व चुनौती के अधीन होने की मांग नहीं की जा रही है और यह केवल बिक्री विलेख की जांच है, जो कि विषय है, इसकी न्यायिक जांच पर इसका क्या असर होगा बिक्री विलेख दिनांक 22 सितंबर 2016 के औचित्य पर न्यायालय द्वारा, धारा 11 को आकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि यह वादी / प्रतिवादी के लिए पूरी तरह से एक अलग और "कार्रवाई का अलग कारण" है, उक्त बिक्री विलेख को चुनौती देने के लिए और केवल इस तथ्य के कारण, कि प्रतिवादी/पुनरीक्षणवादी, भले ही उसके पक्ष में घोषणा का एक डिक्री है, वह सह-प्रतिवादियों द्वारा स्वयं के रूप में निष्पादित किए गए एक विलेख को चुनौती देने से शाश्वतता के लिए प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं करेगा, इसलिए, यह निर्णय, वास्तव में, थोड़ा अलग मुद्दे पर आधारित था, जो उक्त निर्णय के पैरा 2 में की गई टिप्पणियों के आलोक में पूरी तरह से शामिल था। इसे वास्तविक तथ्य से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता है, जो माननीय शीर्ष के समक्ष विचार के लिए इसमें शामिल था।

न्यायालय ने उक्त वाद में जहां मंदिर को निर्देश देने वाले अनिवार्य निषेधाज्ञा के डिक्री के अनुदान का प्रभाव, 4 अक्टूबर 1962 के पत्र में दिए गए वचन का पालन करने के लिए, क्योंकि यह तथ्यात्मक रूप से एक बनाए रखने के प्रयोजनों के लिए उक्त मामले में विचार शामिल था स्वतंत्र और अनन्य कब्जा और मंदिर की विवादित संपत्ति पर आनंद लेना, वह कारण था जिसे पहले के मुकदमे में किए गए फैसले के परिणामस्वरूप माना जा रहा था, जो कि 1981 के उक्त मामले में विचार का विषय था। इसलिए, उक्त मामला पूरी तरह से एक अलग विचार पर आधारित था, जो कि इस न्यायालय द्वारा तय किया जा रहा है। इसलिए, इस न्यायालय की राय के अनुसार, धारा 11 के उक्त सिद्धांत, जैसा कि पैरा 36 में देखा गया है, का अर्थ हमेशा धारा 11 को आकर्षित करना होगा, जब विषय एक ही हो, लेकिन कार्रवाई का कारण पूरी तरह से अलग हो वह भी कार्रवाई का कारण जो बाद में स्वीकार किया गया है।

17. एक अन्य निर्णय, जिसका संदर्भ पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा किया गया है, जैसा कि 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 563, सत्यनाथ और अन्य बनाम सरोजमणि में रिपोर्ट किया गया है, और विशेष रूप से, पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने फिर से उक्त निर्णय के पैरा 27 में परिकल्पित सिद्धांतों पर भरोसा किया है, जिसे पैरा 29 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जहां आदेश 7 नियम 11 के निहितार्थ को आकर्षित करने के कारण लगाए गए है -सीपीसी की धारा 11 के सिद्धांत पैरा 27 और 29 यहां गए उद्धत हैं: -“27 यह न्यायालय इस प्रकार संहिता के आदेश VII नियम 11 के दायरे की जांच कर रहा था, जबकि वर्तमान अपील में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। दरअसल, प्रतिवादी ने प्रारंभिक मुद्दों को तैयार करने के लिए एक आवेदन दायर किया है इसलिए, इस तरह के आवेदन पर संहिता के आदेश XIV नियम 2 के प्रावधानों के आलोक में विचार करने की आवश्यकता है।

29. इस न्यायालय के समक्ष अपील में, यह विचार किया गया था कि क्या न्याय निर्णय कानून और तथ्यों का मिश्रित प्रश्न उठाता है। न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारणा की है:

“26 न्यायालय रेस जुडिकेटा की दलील की प्रयोज्यता का विश्लेषण करते हुए पहले यह निर्धारित करता है कि क्या धारा 11 सीपीसी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है; और यदि इसका उत्तर हां में दिया जाता है, तो यह निर्धारित करना होगा कि पहले मुकदमे के बाद से कानून या तथ्यों में कोई भौतिक परिवर्तन हुआ है या नहीं, जिसके परिणामस्वरूप रेस जुडिकाटा का सिद्धांत लागू नहीं होगा। हम अपीलकर्ताओं की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि रेस जूडिकाटा को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में कभी भी तय नहीं किया जा सकता है। कुछ मामलों में, विशेष रूप से जब कानून या तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न उठाया जाता है, तो सबूत पेश करने के बाद इस मुद्दे को पूर्ण सुनवाई का इंतजार करना चाहिए। वर्तमान मामले में, रेस जुडिकाटा के घटकों का निर्धारण पहले के मुकदमों में दलीलों और निर्णयों को चालू करता है जिन्हें रिकॉर्ड में लाया गया है। ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय अदालत के समक्ष इस आधार पर इस मुद्दे पर बहस की गई है; इसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष दो दौर की कार्यवाही हुई (दूसरा इस आधार पर इस अदालत द्वारा रिमांड के आदेश के बाद कि सभी पक्षों को नहीं सुना गया)। इस मुद्दे को तय करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजी सामग्री अदालत के समक्ष है और उस आधार पर पूरी तरह से लड़ने वाले पक्षों द्वारा तर्कों को संबोधित किया गया है।

62. उपरोक्त चर्चा के आधार पर, हम अपने निष्कर्षों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं:

(i) पश्चातवर्ती मुकदमे में उत्पन्न होने वाले मुद्दे या तो तथ्य या कानून के प्रश्न या कानून और तथ्य के मिश्रित प्रश्न हो सकते हैं। पहले मुकदमे में फैसले के बाद परिस्थितियों में बदलाव के लिए, अगर कोई नया तथ्य सामने आता है, जिसे साबित करना होता है, तो रेस जुडिकाटा की दलील के निर्धारण के लिए मुकदमे की आवश्यकता होगी। हालांकि, रेस जुडिकाटा की याचिका एक में हो सकती है
उपयुक्त मामले को एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए, जब न तो तथ्य के विवादित प्रश्न और न ही कानून या तथ्य के मिश्रित प्रश्न को हल करने के लिए अधिनिर्णित किया जाना है;"

18. निर्णय के सिद्धांत के उक्त प्रश्न का उत्तर देते समय, यह देखा गया है, निर्णय के आलोक में और पैरा 29 में दिए गए तर्क के अनुसार, यदि शामिल है तो निर्णय का मुद्दा कभी भी प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है , विशेष रूप से जब कानून या तथ्य का मिश्रित प्रश्न उठाया जाता है और न्यायालयों द्वारा इसका तुलनात्मक विश्लेषण किया जाना है। कार्यवाही के पक्षकारों द्वारा साक्ष्य अंकित करने के बाद, इस मुद्दे को एक पूर्ण सुनवाई का इंतजार करना चाहिए क्योंकि यह दस्तावेजी साक्ष्य का एक सिधान्त है।

19. इस सिद्धांत को तथ्य के मिश्रित प्रश्न या कानून के मिश्रित प्रश्न के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए, वास्तव में, जो बदली हुई परिस्थितियों में, जो वर्तमान मामले में 22 सितंबर 2016 के बाद के बिक्री विलेख के कारण होता है। , जिसके लिए रेस-जुडिकाटा की दलील के निर्धारण के लिए एक परीक्षण की आवश्यकता होती है, यदि कार्रवाई का एक नया कारण उत्पन्न होता है, अर्थात बिक्री विलेख का निष्पादन, जिसे कानून के अनुसार साबित करना होता है, कि इसे वैध रूप से निष्पादित किया गया है, जब विलेख परिवहन के मामले को ही न्यायालय के समक्ष न्यायिक जांच का विषय बना दिया जाता है।

20. 2014 की सिविल अपील संख्या 5527, कॉफी बोर्ड बनाम मेसर्स रमेश एक्सपोर्ट्स प्रा. लिमिटेड, 2014 (6) एससीसी 424 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बताया गया है, बाद के मुकदमे की संस्था से बनाए जाने वाले बाधा की परिस्थितियों के संबंध में काम कर रहा था, पहले दी गई कार्यवाही में अधिकार के एक अधिनिर्णय के निहितार्थ के रूप में यह देखा गया है कि सीपीसी की धारा 11 के सिद्धांतों को आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के अनुरूप पढ़ा जाना है, यह केवल एक बार पैदा करेगा जब कारण कार्रवाई पहले के मुकदमे में समान थी, जिसे बाद में वादी द्वारा दायर किए गए बाद के मुकदमे में उत्तेजित किया गया था, जो कि मौजूदा मामले में 22 सितंबर 2016 को बिक्री विलेख होता है। उक्त निर्णय का पैरा 11 यहां उद्धत है: -

"11 आदेश 2 नियम 2 की रोक वहां लागू होती है जहां कार्रवाई का कारण जिस पर पिछला मुकदमा दायर किया गया था, बाद के मुकदमे का आधार बनता है; और जब वादी पहले के मुकदमे में बाद के मुकदमे में मांगी गई राहत का दावा कर सकता था; और दोनों वाद एक ही पक्षकार के बीच के हैं। इसके अलावा, आदेश 2 नियम 2 के तहत रोक को मुकदमे में प्रतिवादी द्वारा विशेष रूप से पैरवी की जानी चाहिए और ट्रायल कोर्ट को विशेष रूप से उस संबंध में एक विशिष्ट मुद्दा तैयार करना चाहिए जिसमें पहले के मुकदमे में दलील की जांच की जानी चाहिए और वादी को एक अवसर दिया जाना चाहिए प्रदर्शित करें कि बाद के मुकदमे में कार्रवाई का कारण अलग है। यह इस न्यायालय द्वारा अलका गुप्ता बनाम नरेंद्र कुमार गुप्ता (सुप्रा) में आयोजित किया गया था, जिसमें गुरबक्स सिंह बनाम भूरालाल [4] में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया गया था जिसमें यह माना गया था कि:
"6। कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 2(3) के तहत एक बार की याचिका सफल होनी चाहिए, प्रतिवादी जो याचिका उठाता है उसे यह करना चाहिए: (1) कि दूसरा मुकदमा कार्रवाई के समान कारण के संबंध में था जिस पर पिछला मुकदमा आधारित था; (2) उस वाद हेतुक के संबंध में वादी एक से अधिक अनुतोष का हकदार था; (3) इस प्रकार एक से अधिक अनुतोष के हकदार होने के कारण वादी ने न्यायालय से प्राप्त अनुमति के बिना उस अनुतोष के लिए वाद दायर करने का लोप किया जिसके लिए दूसरा वाद दायर किया गया था। इस विश्लेषण से यह देखा जा सकता है कि प्रतिवादी को मुख्य रूप से कार्रवाई का सटीक कारण स्थापित करना होगा, जिस पर पिछला मुकदमा दायर किया गया था, जब तक कि कार्रवाई के कारण के बीच पहचान न हो, जिस पर पहले का मुकदमा दायर किया गया था और जिस पर बाद के मुकदमे में दावा आधारित है, वहां बाधा की कोई गुंजाइश नहीं होगी।"

21. 2010 (2) SCC 545 में रिपोर्ट किए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 11 के तहत रेस-जुडिकाटा के सिद्धांतों से निपटते समय एक मुद्दे से निपटा है, जबकि बाद के मुकदमे के संस्थापन के निषेध के निहितार्थों पर विचार करते हुए, जो देखने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या दोनों मुकदमों में दावा की गई राहत कार्रवाई के एक ही कारण से उत्पन्न हुई है और यदि कोई अंतर है तो बाद का मुकदमा धारा 11 सी.पी.सी.द्वारा वर्जित नहीं होगा।

22. चूंकि यहां, बाद के बिक्री विलेख के कारण कार्रवाई का कारण उत्पन्न हो रहा है, यह दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के तहत इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के अनुसार पूरी तरह से एक अलग मुद्दा होगा इसलिए, सीपीसी की धारा 11 की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक सामग्री हैं: -

(i) मामला पहले के मुकदमे में सीधे और पर्याप्त रूप से जारी होना चाहिए और बाद के मुकदमे में, जो यहां सम्भव नहीं है, क्योंकि यहां एक बिक्री विलेख था, जो जांच का विषय था, जहां इस न्यायालय द्वारा पहले ही निर्धारित किया जा चुका था।

(ii) इस तथ्य के बावजूद एक पूर्व मुकदमा, कि यह पार्टियों के एक ही समूह या उनके तहत दावा करने वाले व्यक्ति के बीच होना चाहिए, लेकिन फिर भी केवल इसलिए कि यह पार्टियों का एक ही समूह है, जो बाद के मुकदमे में मुकदमेबाजी कर रहे हैं, जो आमतौर पर संपत्ति के संबंध में पहले की कार्यवाही में भी पक्षकार थे। यहां "मुद्दा" हमेशा बाद के "कार्रवाई के कारण" को निरूपित करेगा। इसलिए, इस मामले को ध्यान में रखते हुए, चूंकि बाद का मुकदमा कार्रवाई के एक नए कारण के कारण उत्पन्न हो रहा था, जो कि बाद के बिक्री विलेख के निष्पादन के कारण अर्जित हुआ है, धारा 11 की बाधा लागू नहीं होगी, क्योंकि मामला अभी भी पहले के डिक्री के प्रभाव के बारे में न्यायालय द्वारा निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ दिया जाएगा।

23. यदि आक्षेपित निर्णय पर विचार किया जाता है, तो धारा 11 के तहत पुनरीक्षणवादी के आवेदन को खारिज करते हुए सक्षम न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क पूरी तरह से न्यायोचित हैं, क्योंकि इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि धारा 11 को आकर्षित करने के प्रयोजनों के लिए, यह हमेशा एक "मुद्दा", यानी "कार्रवाई का कारण" होगा, जो एक प्रमुख विचार का होना चाहिए और विशेष रूप से सूट या विषय वस्तु के पक्ष नहीं, जो कि पूर्व कार्यवाही में मुकदमेबाजी के तहत था। यहां, कार्रवाई का कारण, जैसा कि यह पहले ही देखा जा चुका है, बाद की बिक्री विलेख है,अतः सीपीसी की धारा 11 या आदेश 7 नियम 11 की बाधा यहां आकर्षित नहीं होगी इसलिए, मुझे पुनरीक्षण में कोई योग्यता नहीं दिखती है। तद्नुसार पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है।

(शरद कुमार शर्मा, जे.)
20.07.2022